भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5310

जिसका उत्तर 25 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

04 चैत्र, 1948 (शक)

उत्तर प्रदेश में 'पीएमजीदिशा' और सीएससी पहल

5310. श्री राजीव रायः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-26 के दौरान घोसी निर्वाचन क्षेत्र सहित मऊ जिले में कितने सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) कार्य कर रहे हैं और कौन-सी सेवाएं प्रदान की जा रही है

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) उत्तर प्रदेश में (पीएमजीदिशा) और सीएससी से संबंधित पहलों के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई है और मऊ जिले में कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या किसी समीक्षा या मूल्यांकन में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच खामियों अथवा संपर्कता संबंधी चुनौतियों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घोसी में डिजिटल पहुंच और डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** वित्तीय वर्ष 2024-26 के दौरान मऊ जिले में कार्यात्मक सीएससी की संख्या इस प्रकार है:

जिले का नाम	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
घोसी निर्वाचन क्षेत्र सहित मऊ	1,240	1,260	1,256

<u>वितरित की गई सेवाएं:</u>

इन सीएससी के माध्यम से नागरिकों को 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें गवर्मेंट -टू-सिटीजन (जी2सी), बिजनेस-टू-सिटीजन (बी2सी), वित्तीय सेवाएं, बीमा सेवाएं आदि शामिल हैं। सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण https://csc.gov.in/ पर देखा जा सकता **है।**

सामान्य सेवा केंद्र परियोजना पूरे भारत में कार्यान्वित की गई है। ये सीएससी एक आत्मनिर्भर और उद्यमिता मॉडल पर स्थापित किए गए हैं, जो ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा चलाए जाते हैं। सीएससी परियोजना को सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत अखिल भारतीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है। यह परियोजना 31.03.2024 से सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।

<u>प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):</u>

सरकार ने देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए पीएमजीदिशा शुरू की। देश भर में कुल 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में इस योजना के तहत कुल 1,65,906 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। यह योजना 31.03.2024 को समाप्त हो गई है।

पीएमजीदिशा योजना और सीएससी के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया है, जिसका निष्कर्ष है:

- पीएमजीदिशा के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों को अपनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचना और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक उनकी पहुंच को सक्षम करके प्रतिभागियों को लाभान्वित किया, जिससे देश में समग्र डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिली
- वीएलई की सामाजिक स्थिति के साथ-साथ नागरिकों को सेवा वितरण में आसानी पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव। वीएलई न केवल उद्यमी हैं, बल्कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो समुदायों और देश के समग्र विकास और सामाजिक ताने-बाने में योगदान दे रहे हैं। सीएससी ने नागरिकों को सीएससी के माध्यम से सहायता प्राप्त मोड में व्यापक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में मदद की है।

डिजिटल पहुंच और डिजिटल साक्षरता को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक निकाय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) के माध्यम से डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम प्रदान करना
- वर्तमान में, नाइलिट के पास सूचना, शिक्षा, संचार और प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) क्षेत्रों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए 56 केंद्र और 700 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों के साथ-साथ 8,500 से अधिक सुविधा केंद्र हैं
- उत्तर प्रदेश राज्य में, नाइलिट के 4 केन्द्र गोरखपुर, लखनऊ, पीलीभीत और नोएडा में स्थित हैं। इसके अलावा, नाइलिट के पास विभिन्न स्तरों के डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए राज्य भर में फैले 4,000+ सुविधा केंद्र हैं
- मऊ जिले में, नाइलिट के 75+ डिजिटल साक्षरता सुविधा केंद्र हैं, जिनमें घोसी में स्थित 12 केंद्र शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में, राज्य भर में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों में नाइलिट द्वारा 21 लाख+ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सेवा वितरण और डिजिटल पहुंच को मजबूत करने के लिए लगातार विभिन्न पहल कर रहा है, जो इस प्रकार है:

- सेवा की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए वीएलई के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) और नागरिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया।
- सीएससी की परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर नियमित क्षेत्र दौरे और निगरानी।
- प्रत्येक सीएससी पर लेनदेन और सेवा वितरण को ट्रैक करने के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी।
- प्रतिस्पर्धात्मकता और बेहतर सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए वीएलई प्रदर्शन/रैंकिंग के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया।

***